राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 996/2005

प्रेमराज पुत्र अम्बालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम झूठा, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य

2. शांतिलाल पुत्र सुजानमल, जाति महाजन, निवासी ग्राम डाबला, जिला भीलवाड़ा।

3. सुगनचंद पुत्र मघराज, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम झूठा, थाना रायपुर, जिला पाली।

4. महावीर चंद पुत्र मघराज, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम झूठा, थाना रायपुर, जिला पाली।

5. देवीचंद पुत्र मघराज, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम झूठा, पुलिस थाना रायपुर, जिला पाली।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: सुश्री योगिता मोहनानी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, पी.पी.

श्री हरीश के लिए श्री शशांक शर्मा पुरोहित (नि.सं. 2 से 5)।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश(मौखिक)</u>

<u>28/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने सत्र प्रकरण संख्या 70/2005 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक नं.1), पाली मुख्यालय, जैतारण, जिला पाली द्वारा दिनांक 08.04.2005 को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, बार, जिला पाली द्वारा दिनांक 24.07.1999 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय को संशोधित किया गया था, जैसा कि बाद में उल्लेख किया गया है।

2. इस याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि रायपुर थाने की पुलिस ने गैर याचिकाकर्ताओं संख्या 2 से 5 और मंगू गिरी तथा आदूराम के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, बार की अदालत में धारा 147, 148, 451, 323, 324, 325, 326 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत चालान पेश किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और उन्हें इन अपराधों के लिए अलग-अलग अवधि के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी मंगू गिरी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।

2.1 गैर-याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 ने अपील दायर की, जिसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1, पाली में हुई। विद्वान अपीलीय न्यायाधीश ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। विद्वान न्यायाधीश ने शांतिलाल को सभी अपराधों से बरी कर दिया। उन्होंने अन्य गैर-याचिकाकर्ताओं/आरोपियों को धारा 326/149, 148, 451 के तहत अपराधों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें धारा 324, 325, 323, 447 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए दोषी

ठहराया और उन्हें परिवीक्षा पर रिहा कर दिया। दोषी आदूराम की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है और आरोपित आदेश का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि गैर-याचिकाकर्ताओं को आईपीसी की धारा 326/149, 148, 451 और अन्य आरोपों के तहत अपराधों के लिए बरी करना कानून के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने घायल गवाह की गवाही और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया कि प्रेमराज के सिर पर लगी चोट आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए तेज धार वाले हथियार से लगी थी और मेडिकल अधिकारी ने इसे गंभीर माना। चूंकि सभी आरोपी घातक हथियारों से लैस एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें आईपीसी की धारा 326/149 के तहत सही ढंग से दोषी ठहराया गया। हालांकि, अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि चोट किसी कुंद हथियार (हॉकी स्टिक) से पहुंचाई गई थी, निराधार, त्रुटिपूर्ण है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने शांतिलाल को गैरकानूनी सभा में उसकी भागीदारी के साक्ष्य के बावजूद गलत तरीके से बरी कर दिया। नतीजतन, आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोपी को बरी करना अवैध है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

5. मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अपनाए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। आरोपित आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, इस तर्क पर आधारित है कि अभियोजन पक्ष ने आक्रामक कार्यों या अवैध सभा बनाने में आरोपी / महावीर चंद की भागीदारी को निर्णायक रूप से साबित नहीं किया।

नतीजतन, आरोपी की भागीदारी के बारे में सबूत संदिग्ध थे। केवल सुगनचंद, महावीर प्रसाद और देवीचंद ही उचित संदेह से परे अपराध में शामिल साबित हुए। शांतिलाल, आदू और मंगूपुरी की संलिप्तता स्थापित नहीं हुई।

5.1 शेष अभियुक्तों-सुगनचंद, महावीर प्रसाद, देवीचंद और शांतिलाल के लिए शांतिलाल की विशिष्ट भूमिका साबित नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें धारा 147, 148, 451/149, 323, 324/149, 325 और 326/149 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। इसे व्यक्तिगत लड़ाई का मामला माना गया जो कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुआ था और प्रत्येक अभियुक्त को केवल उनके विशिष्ट कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

5.2 महावीर प्रसाद को धारा 324 आईपीसी के तहत अपराध करते हुए पाया गया, जिसमें दीपचंद और प्रेमराज को चोटें आईं। सुगनचंद को धारा 325 और 323 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया, और देवीचंद को धारा 325 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया। धारा 451 आईपीसी के तहत आरोप को धारा 447 आईपीसी से बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप महावीर प्रसाद को धारा 324 और 447 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया, जबकि उन्हें अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया। सुगनचंद को कई आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन धारा 325 और 323 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया। देवीचंद को धारा 325 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया और अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया।

6. ऊपर जो कुछ भी उल्लेख किया गया है, उस पर विचार करने के बाद, मैं विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में व्यक्त तर्क से सहमत हूं। गहन समीक्षा के बाद, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिला, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान कानून या तथ्यात्मक निष्कर्षों में कोई अनियमितता नहीं बताई गई है। वकील ने कानूनी मानदंडों

या तथ्यात्मक त्रुटियों से कोई विचलन नहीं दिखाया है जो विचाराधीन आदेश पर पुनर्विचार का कारण बने। इसलिए, विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए तर्क और निष्कर्ष ठोस प्रतीत होते हैं और साक्ष्य और लागू कानून द्वारा अच्छी तरह से समर्थित हैं।

7. धारा 147, 148 और 149 आईपीसी के तहत बरी होना उचित है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि सभी आरोपी कथित अपराध करने के लिए एक समान इरादे से एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा थे। इन धाराओं के तहत दोषसिद्धि के लिए, आरोपियों के बीच साझा उद्देश्य का स्पष्ट सबूत होना चाहिए, जो इस मामले में निर्णायक रूप से प्रदर्शित नहीं हुआ। अपीलीय अदालत का तर्क कि घटना के दौरान कुछ आरोपियों को किसी विशेष आक्रामक कार्रवाई से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था, कानूनी रूप से सही है।

8. इसके अलावा, अपीलीय अदालत ने पीड़ित प्रेमराज को लगी चोटों की प्रकृति के बारे में सबूतों में विसंगतियां पाईं। जबकि ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चोट एक तेज धार वाले हथियार से लगी थी, अपीलीय अदालत ने निर्धारित किया कि सबूत हॉकी स्टिक जैसी किसी कुंद वस्तु के इस्तेमाल की ओर इशारा करते हैं। चिकित्सा साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित नहीं किया कि चोटों का कारण धारदार हथियार था। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथियार का वर्गीकरण सीधे तौर पर धारा 326/149 आईपीसी की प्रयोज्यता को प्रभावित करता है, जो खतरनाक हथियारों से होने वाली गंभीर चोटों से संबंधित है। शांतिलाल के लिए, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य उसके द्वारा किए गए किसी भी विशिष्ट कार्यों को दिखाने में विफल रहे, जो कथित आरोपों के तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराते हों। कथित गैरकानूनी सभा में उसकी सक्रिय भागीदारी या नेतृत्व के स्पष्ट सबूत के बिना, उसे बरी करने का सत्र न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से सुसंगत है।

9. धारा 324, 325, 323 और 447 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए संशोधित दोषसिद्धि अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उचित सराहना को दर्शाती है। कानून की आवश्यकता है कि प्रत्येक आरोपी को उन विशिष्ट कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए जो उचित संदेह से परे साबित होते हैं। न्यायालय ने महावीर प्रसाद, सुगनचंद और देवीचंद को विशिष्ट अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया, जहां साक्ष्यों से पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाया, इस प्रकार आपराधिक कानून में व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सिद्धांत को बरकरार रखा।

10. जहां तक दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्णय है, यह पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है, विशेष रूप से मामले की परिस्थितियों और अपराधों की प्रकृति को देखते हुए। जिन अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था, वे गंभीर श्रेणी के नहीं हैं, और इस प्रकार परिवीक्षा प्रदान करना अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के तहत न्यायिक विवेक के अनुरूप है।

11. आधार में, पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और तदनुसार खारिज किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के अनुसार मुआवजा/जुर्माना दिया जाना है।

12. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।